स्वजलधारा

क्या सबको पानी मिलेगा?

रेखा कृष्णन

भारत के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के मकसद से तमाम नीतियां बनी हैं और कार्यक्रम चलाए गए हैं - मसलन, 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया गया था जिसका नाम 1991 में बदलकर राजीव गांधी पेयजल मिशन कर दिया गया था। इसके अलावा त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय कार्यक्रम भी चलाया गया। इस केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का मकसद यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 40 लीटर सुरक्षित पेयजल मिल पाए और 30 लीटर पानी प्रति पशु भी उपलब्ध हो पाए। लक्ष्य यह था कि हर 250 व्यक्तियों पर एक जल स्रोत हो, मैदानी इलाकों में हरेक बस्ती के 1.6 किलोमीटर के दायरे में और पहाड़ी इलाकों में 100 मीटर की चढ़ाई के अंदर पेयजल स्रोत हो।

हाल ही में टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी) ने राष्ट्र संघ जनसंख्या कार्यक्रम के वित्तीय सहयोग से यह जानने के लिए एक अध्ययन किया कि पानी और जीवन की गुणवत्ता पर जनसंख्या वृद्धि का क्या असर होता है। टेरी के अध्ययन से पता चलता है कि उपरोक्त कार्यक्रमों का असर तो हुआ है मगर सचमुच परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं। जिन स्थानों पर पानी सम्बंधी योजनाएं तैयार भी हुई हैं वहां भी कई अन्य कारक ऐसे हैं जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं आने देते। अध्ययन में 4 ज़िलों के 20 गांवों को शामिल किया गया था - सोलन (हिमाचल), तिरुअनंतपुरम (केरल), रायचूर (कर्नाटक) और बीकानेर (राजस्थान)।

अध्ययन में करीब 350 परिवारों का सर्वेक्षण किया गया और विभिन्न समूहों (जैसे महिलाओं, किसानों, बुजुर्गों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों तथा स्वास्थ्यकर्मियों) से चर्चा भी की गई। मूलतः निम्नलिखित मुद्दों पर जानकारी एकत्रित करके विश्लेषण किया गया: जनांकिकी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति, पानी की ज़रूरत, उपलब्धता और उपभोग; पानी प्राप्त करने में लगा श्रम, महिलाओं व बच्चों की भूमिका, पानी की गुणवत्ता को लेकर लोगों के एहसास और परीक्षण और पानी की गुणवत्ता का स्वास्थ्य से सम्बंध। हर जगह पानी की अम्लीयता, क्षारीयता, फ्लोराइड, अवशिष्ट, क्लोरीन, क्लोराइड, गंदलापन, नाइट्रेट, फॉस्फोरस, लौह और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के परीक्षण भी किए गए। इस अध्ययन से पानी की समस्या व उसके प्रभाव को लेकर कई बातें पता चलती हैं। यह भी स्पष्ट होता है कि अलग-अलग क्षेत्रों में और यहां तक कि एक ही क्षेत्र के अलग-अलग गांवों में ये समस्याएं काफी अलग-अलग स्तर व प्रकृति की हैं।

लगभग सभी सर्वेक्षित गांवों में पानी की कमी की बात तो सामने आई मगर यह भी पता चला कि अलग-अलग क्षेत्रों में स्थिति बहुत अलग-अलग है। मसलन बीकानेर और रायचूर के गांवों में तो पीने के पानी का भी घोर अभाव था जबकि सोलन में प्रमुख समस्या सिंचाई के पानी की थी। अचरज की बात यह है कि तिरुअनंतपुरम में सामान्यतः पर्याप्त पानी है मगर यहां भी कुछ परिवारों ने पानी के अभाव की बात कही।

सर्वेक्षण से पता चला कि जहां तिरुअनंतपुरम में नज़दीकी जल स्रोत से परिवारों की औसत दूरी 60 मीटर है, वहीं बीकानेर में यह दूरी 6 किलोमीटर है। नतीजा यह है कि तिरुअनंतपुरम में एक परिवार को पानी प्राप्त